



2026:AHC:66869-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

पहली अपील दोषपूर्ण संख्या- 58 वर्ष 2026

बृजेंद्र कुमार यादव @ बृजेंद्र यादव अपीलकर्ता

बनाम

श्रीमती पूनम यादव प्रतिपक्षी

अपीलकर्ता के अधिवक्ता: आलोक कुमार श्रीवास्तव, श्वेता श्रीवास्तव

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: ----

न्यायालय सं - 2

माननीय न्यायमूर्ति श्री अतुल श्रीधरन

माननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक सरन

- वर्तमान अपील अपीलकर्ता द्वारा अतिरिक्त प्रधान परिवार न्यायालय न्यायाधीश, वाराणसी की अदालत द्वारा केस संख्या-1493 वर्ष 2024 में पारित निर्णय और डिक्री दिनांक 10.12.2025 के खिलाफ दायर की गई है, जिसके तहत अपीलकर्ता को एकपक्षीय कार्यवाही की गई थी और प्रतिपक्षी-पत्नी को विवाह की अशक्तता की डिक्री दी गई थी, जो उस समय अपीलकर्ता के पहले से मौजूद विवाह के आधार पर परिवार न्यायालय के समक्ष वादी थी, जब अपीलकर्ता ने प्रतिपक्षी/वादी के साथ विवाह किया था।
- अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने कहा है कि इस मामले के निर्विवाद तथ्यात्मक पहलू यह हैं कि अपीलकर्ता की शादी पहले एक 'X' से हुई थी (महिला का नाम उसकी गोपनीयता की रक्षा के लिए नहीं दिया जा रहा है) और क्योंकि अपीलकर्ता और 'X' के बीच कुछ मतभेद पैदा हुए थे, जो पति और पत्नी हैं, उन्होंने विवाह को भंग करने का फैसला किया और हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B के तहत संयुक्त रूप से तलाक की याचिका संख्या-882 वर्ष 2023 दायर की।



3. हालांकि, यह भी निर्विवाद तथ्य है कि अपीलकर्ता के 'X' के साथ विवाह के निर्वाह के दौरान, उसने 20.12.2022 को कल्याणपुर, कानपुर नगर में आर्य समाज विवाह करके प्रतिपक्षी/वादी के साथ विवाह किया। इसके दो साल बाद 10.04.2024 को, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, न्यायालय संख्या-5, प्रयागराज की अदालत ने अपीलकर्ता और 'X' को आपसी सहमति से तलाक दे दिया। जब प्रतिपक्षी को उक्त पहले से मौजूद विवाह के बारे में पता चला, जिस पर अपीलकर्ता को आपसी सहमति से तलाक दिया जा रहा है, तो उसने प्रतिपक्षी के साथ विवाह संपन्न करने के समय अपीलकर्ता के पहले से मौजूद विवाह के कारण अपने विवाह की अशक्तता की घोषणा के लिए धारा 11 के तहत मामला दायर किया। इस मामले में, अपीलकर्ता को नोटिस जारी किया गया था, जिसने विचारण न्यायालय के समक्ष बचाव किया था, जिसे अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया था कि उसके मुवक्किल को कभी नहीं मिला। इसके बाद, विचारण न्यायालय के आदेश में यह दर्ज किया गया है कि प्रतिस्थापित सेवा को समाचार पत्र में प्रकाशन द्वारा प्रभावित किया गया था, जो एक धारणा पैदा करता है कि अपीलकर्ता विवाह को अमान्य घोषित करने के लिए विद्वान परिवार न्यायालय के समक्ष मौजूद कार्यवाही की जानकारी में था। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 के तहत उक्त मामला प्रतिपक्षी-पत्नी द्वारा 07.08.2024 को, आपसी सहमति से तलाक की डिक्री दिए दायर किया गया था। इसके बाद, अवर न्यायालय ने सबूत पेश करने और आश्वस्त करने के बाद कि अपीलकर्ता ने 'एक्स' के साथ विवाह के निर्वाह के दौरान प्रतिपक्षी से शादी की थी, ने प्रतिपक्षी की शादी को अपीलकर्ता से अमान्य घोषित कर दिया।

4. अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि उन्हें हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 के तहत कार्यवाही के बारे में कभी पता नहीं था और उन्हें 10.12.2025 का आक्षेपित आदेश पारित होने के बाद ही पता चला। उन्होंने आगे तर्क दिया है कि प्रतिपक्षी ने इस तथ्य को स्वीकार कर लिया था कि जब उसने 21.12.2022 को प्रतिपक्षी से शादी की थी तो वह पहले से ही 'एक्स' से शादी कर चुका था। इन परिस्थितियों में, अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि प्रतिपक्षी की ओर से सहमति थी और इसलिए उसे



अशक्तता के लिए मामला दायर करके अपीलकर्ता के सामने अपनी शादी को चुनौती देने के कार्य से रोक दिया गया था।

5. अपीलकर्ता के अधिवक्ता को सुनने के बाद, जो निर्विवाद रूप से सामने आता है वह यह है कि अपीलकर्ता की शादी 'एक्स' से हुई थी और यह विवाह 21.12.2022 को भी जीवित था जब अपीलकर्ता ने प्रतिपक्षी से शादी की थी। जहां तक विचारण न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के ज्ञान की कमी का संबंध है, यह न्यायालय अपीलकर्ता के अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों से आश्वस्त नहीं है। उन्होंने इस तथ्य को चुनौती नहीं दी है कि कागजी प्रकाशन के माध्यम से नोटिस की प्रतिस्थापित सेवा का सहारा लिया गया था, इसके अलावा, वर्तमान अपील 05.01.2026 को दायर की गई है, यानी आक्षेपित आदेश पारित होने के एक महीने से भी कम समय बाद। ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता कार्यवाही के लंबित होने के बारे में पूरी तरह से जानता था और यही कारण है कि वर्तमान अपील विचारण न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश पारित होने के एक महीने के बाद भी दायर की गई थी।

6. जहां तक अपीलकर्ता के अधिवक्ता के तर्क का संबंध है कि प्रतिपक्षी ने अपनी पहले की शादी को स्वीकार कर लिया है और उसके बाद ही अपीलकर्ता के साथ विवाह कर लिया है और इसलिए उसे इस आधार को उठाने से रोक दिया गया है, यह भी इस न्यायालय में अपील नहीं करता है। धारा 11 शून्य विवाह की शून्यता की डिक्ली द्वारा घोषणा का प्रावधान करती है। शून्य विवाह वे हैं जो धारा 5 के खंड (i), (iv) और (v) में निर्दिष्ट प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। धारा 5(i) में कहा गया है कि विवाह दो हिंदुओं के बीच संपन्न किया जा सकता है जहां विवाह के समय किसी भी पक्ष का पति या पत्नी नहीं है।

7. इस प्रकार, जहां विवाह धारा 5(i) के तहत आता है, वहां कोई सहमति नहीं हो सकती है। यह मानते हुए कि प्रतिपक्षी ने पूरी तरह से अच्छी तरह से जानते हुए विवाह के लिए सहमति दे दी थी कि अपीलकर्ता ने पहले ही कहीं और शादी कर ली थी और इस घटना में, दोनों के बीच कोई तलाक नहीं हुआ था, इस तरह की स्वीकृति के बावजूद प्रतिपक्षी की स्थिति अमान्य होती क्योंकि यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि दूसरी पत्नी हिंदू विवाह अधिनियम के तहत कानूनी नहीं है। यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि



कानून के खिलाफ कोई एस्टोपेल नहीं हो सकता है, इसलिए जो कानून स्वयं शुरुआत में प्रतिबंधित करता है, उसे किसी एक पक्ष की सहमति के माध्यम से वैध नहीं किया जा सकता है।

8. इन परिस्थितियों में, इस न्यायालय के समक्ष अग्रेषित तर्कों को ध्यान में रखते हुए, निर्विवाद तथ्य जिन्हें यहां ऊपर संदर्भित किया गया है, यह कार्यवाही में निरर्थकता होगी क्योंकि आक्षेपित आदेश में कोई त्रुटि स्पष्ट नहीं है, इसलिए, इस न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है और इस तरह, पहली अपील **खारिज** की जाती है।

मार्च 30, 2026

आर.एस. तिवारी

(न्यायमूर्ति विवेक सरन) (न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन)